और हथकरघा क्षेत्र के लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा निर्मित कपड़े की न केवल मात्रा अधिक है बल्कि यह कपड़ा मिलों द्वारा निर्मित कपड़े की तुलना में सस्ता भी है और विद्युतकरघा उद्योग अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता रखता है ;

(घ) यदि हां, तो कपड़ा मिलों की अपेक्षा विद्युतकरघा क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन न दिये जाने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले में नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) सरकार वस्त्र उद्योग के सभी तीनों क्षेत्रों के उनके सहज बल को मद्देनजर रखते हुए उनके विकास के प्रति वचनबद्ध है। मिल क्षेत्र और विद्युतकरघा क्षेत्र के बीच कोई भी भेदभाव नहीं है।

अमरीका में सिले-सिलाए भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हानि

2046. **श्री अजीत जोगी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन द्वारा सिले-सिलाए भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिये जाने के कारण सिले-सिलाए कपड़ों के स्थापित निर्यातकों को भारी घाटा उठाना पड़ा जैसा कि 7 जनवरी, 1993 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमरीकी प्रशासन द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने के क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) अमरीकी सरकार ने अक्तूबर/नवम्बर, 1992 में परिधान की दो श्रेणियों अर्थात् काटन लेडीज ब्लाउजिस एण्ड शर्ट्स (श्रेणी 341) तथा काटन एण्ड मैन मेड फाइबर जैन्ट्स शर्ट्स (श्रेणी 340/640) पर इस आधार पर प्रतिबन्ध लगाया था कि भारत ने इन दोनों श्रेणियों के लिए वर्ष 1992 के कोटा स्तर का पूरा उपयोग कर लिया था तथा अमरीका में और आयात करने की यदि उसे अनुमति दी जाती है तो उससे अत्यधिक लदान करना पड़ेगा। इस प्रतिबन्ध के कारण कुछ निर्यातक अपने वैध कोटाओं का उपयोग नहीं कर सके। तथापि, ऐसे निर्यातकों को हुए घाटों के बारे में सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

Proposals of Restarting Closed Textile Mill Under Co-operatives

2047. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have received proposals from Labour Organisation to restart closed Textile Mills under the co-operative sector;

(b) if so, what is the number of such proposals received from the State of Maharashtra; and

(c) whether Government have taken any decision in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) Some proposals have been received from time to time to re-start closed textile mills under the cooperative sector. Government is willing to support any concrete, viable proposal for co-operativisation of closed textile mills.

वस्त्र उद्योग में सुधार

2048. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष वस्त्र उद्योग की स्थिति में सुधार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बंद मिलों की संख्या, जोकि अक्तूबर, 1992 में 140 थी, चालू वर्ष में कम होकर 123 रह गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपड़े का उत्पादन करने वाली इकाइयों को 750 करोड़ रुपये आबंटित किये थे, जिसमें से 710 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों और शेष धनराशि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई थी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1992 में बन्द पड़ी हुई 149 मिलों की तुलना में 22 सूती/मानवनिर्मित फाइबर वस्त्र मिलें समापन की ओर बढ़ ही है(कम्पनी अधिनियम) तथा बंद पड़ी है रतथा 31-5-93 की स्थिति अनुसार विभिन्न कारणों से 100 सूती/मानवनिर्मित फाइबर वस्त्र मिलें अस्थाई रूप से बन्द पड़ी है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वस्त्र मिलों को आधुनिकीकरण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए 750 करोड़ रु० की धनराशि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वावधान में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना स्थापित की है तथा फरवरी, 1993 तक 875.24 करोड़ रु० वितरित कर दिए गए हैं।

क्षेत्रवार वितरण निम्नोक्त अनुसार है :—

निजी	762.29 करोड़ रु०
सरकारी	77.53 करोड़ रु०
सहकारी	35.42 करोड़ रु०

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को 820.14 करोड़ रु० (योजना तथा गैर-योजना) तथा विद्युतकरघा क्षेत्र को 2 करोड़ रु० प्रदान किए थे। तथापि, यह राशि वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना से नहीं दी गई थी।

हथकरघा और बिजलीकरघा क्षेत्रों में उत्पादन

2049. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कपड़ा उद्योग में बिजलीकरघा क्षेत्र की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में अधिक लोग कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकरों की अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिजली-करघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन देश में कपड़े के कुल उत्पादन का लगभग 72 प्रतिशत होता है जबकि हथकरघा क्षेत्र का उत्पादन केवल 18 प्रतिशत है ;